eISSN 2581-8996
ONLINE
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED JOURNAL
Volume 08, Issue 02, July 2025

उच्च शिक्षा का उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण

डॉ. सौरभ सिंह[1]
[1]सहायक प्राध्यापक शिक्षा विभाग, लाला महादेव प्रसाद वर्मा बालिका महाविद्यालय, लखनऊ

Received: 20 July 2025, Accepted: 25 July 2025, Published with Peer Reviewed on line: 31 July 2025

Abstract

आज का युग वैश्वीकरण का युग है, जिसनें व्यक्ति, समाज व राष्ट्र को सभी क्षेत्रों में प्रभावित किया है। व्यक्ति, समाज या राष्ट्र की प्रगति का अन्दाजा उसकी शिक्षा व्यवस्था से लगाया जा सकता है। यदि किसी देश को बर्बाद करना है तो उसकी शिक्षा व्यवस्था को नष्ट कर दीजिए वह देश स्वतः ही नष्ट/बर्बाद हो जायेगा। किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था में उच्च शिक्षा का वही स्थान होता है, जो मानव शरीर में हृदय का होता है। उच्च शिक्षा का तात्पर्य 10़2 के बाद महाविद्यालयों या विश्वविद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा से है, जो ज्ञान का उत्पादन व प्रसारण करती है। लेकिन बदलाव के इस दौर में विश्वविद्यालय ज्ञान के उत्पादन के एकाधिकार के साथ–साथ समाज में अपना विशिष्ट स्थान भी खोते जा रहे हैं। सहपाठी समूह व स्व–अध्ययन का चलन बढ़ता जा रहा है, केवल विश्वविद्यालय ही ज्ञानार्जन ध सीखने के स्रोत नहीं रहे और न वह सभी की आजीवन सतत् शिक्षा, तकनीकी क्षमता व व्यवसायिक प्रशिक्षण की जिम्मेदारी उठा सकते हैं। अत उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उदारीकरण, निजीकरण व भूमण्डलीकरण को लागू करने हेतु भारत सरकार को बदलते वैश्विक परिदृश्य में उचित नीति का निर्धारण कर, लचीली प्रगतिशील शिक्षा व्यवस्था अपनाने, सृजनात्मक विचारों को बढ़ावा देने, उच्च शिक्षा के व्यापारीकरण व बाजारीकरण को कानून बनाकर रोकने, शैक्षिक, सामाजिक व आर्थिक विषमता कम करने, गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की पहुंच जनसामान्य तक सुनिश्चित करने, उच्च शिक्षा के प्रसारण व उचित प्रबन्धन हेतु सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) मॉडल को सावधानीपूर्वक लागू करने की आवश्यकता है।

संकेत शब्द :– उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण

Introduction

नई आर्थिक नीति 1991 के लागू होने के फलस्वरूप भारत में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण का प्रादुर्भाव हुआ, हालांकि उदारीकरण व वैश्वीकरण के बीज भारत के ष्वसुधैव कुटुम्बकमष् के सूत्र वाक्य से भी दृष्टिगोचर होते हैं, जिसे नये कलेवर के साथ आमूल–चूल परिवर्तन कर प्रस्तुत किया गया और इसके प्रभाव से शिक्षा जगत भी अछूता न रहा। उदारीकरण का तात्पर्य नियमों व प्रतिबन्धों में सरकार या नियामक संस्था द्वारा ढील देने से है। शिक्षा में उदारीकरण का तात्पर्य शिक्षा के क्षेत्र में उदारीकरण के नियमों व प्रतिबन्धों को लागू करने से है, अर्थात शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व संचालन के साथ–साथ शैक्षिक कार्यक्रमों के नियोजन, कार्यान्वयन व पर्यवेक्षण में उदार दृष्टिकोण अपनाने से है, उदारीकरण को शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण की दिशा में सकारात्मक प्रयास माना जाता है, जो शिक्षा व्यवस्था को रूढ़िवादी दृष्टिकोण से छुटकारा दिलाकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, वंचितों, महिलाओं, निर्धनों आदि सभी को गुणवत्तापरक प्रगतिशील शिक्षा प्रदान करने की अपेक्षा से युक्त है।

eISSN 2581-8996
ONLINE
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED JOURNAL
Volume 08, Issue 02, July 2025

शिक्षा अपनी प्रकृति में निजी उपक्रम है, फ्रांस की क्रान्ति से पहले यह प्रायः निजी व्यक्तियों द्वारा दी जाती थी, बाद में इसका सरकारीकरण होता गया। भारत सरकार नें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया और शिक्षा की व्यवस्था करना केन्द्र सरकार व राज्य सरकार का संयुक्त उत्तरदायित्व बना दिया। इसके बावजूद सरकार उच्च शिक्षा की व्यवस्था करने में नाकाम रही, जिसका एक प्रमुख कारण वित्तीय संसाधनों का अभाव था। अतः सरकार नें आवश्यक वित्तीय संसाधन जुटाने व गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का प्रसार करने हेतु शिक्षा के क्षेत्र में भी उदारीकरण की नीति अपनायी और उच्च शिक्षा का क्षेत्र निजी क्षेत्र के लिए भी खोल दिया और नियमों व प्रतिबन्धों में ढील दी गई, परिणामस्वरूप पूंजीपतियों नें भी शिक्षा के क्षेत्र में निवेश करना प्रारम्भ किया जो उनके लिए निवेश का बड़ा क्षेत्र बनकर उभरा और निजीकरण का सूत्रपात हुआ।

निजीकरण शब्द के प्रथम बार प्रयोग का उल्लेख पीटर एफ. ड्रकर की पुस्तक द एज आफ डिस्कन्टीन्युटी में मिलता है। इसके बाद उद्योग, व्यापार, शिक्षा के क्षेत्र में इसका प्रसार होता चला गया। उच्च शिक्षा में निजीकरण का तात्पर्य उच्च शिक्षा के स्वामित्व, संचालन व प्रबन्धन को सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र की ओर हस्तान्तरित करने से है। इसमें शिक्षा के प्रसार व गुणात्मक सुधार की संकल्पना निहित रहता है। भारत भी निजीकरण की इस बयार से अलग न रह सका आज उद्योग, व्यापार, शिक्षा आदि सभी क्षेत्रों में निजीकरण का दबदबा दिखायी देता है। शिक्षा के क्षेत्र में निजी निवेश इतनी तीव्र गति से बढ़ रहा है कि इसने 'उद्योग' का रूप ले लिया है। आज उच्च शिक्षा व्यक्ति, समाज व राष्ट्र के विकास में निर्णायक भूमिका निभाने की बजाय स्वयं करोड़ों डालर का व्यापार बन गयी है। जिसमें सार्वजनिक व निजी क्षेत्र दोनों ही संलिप्त हैं तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ उच्च शिक्षा के क्षेत्र को उभरते हुए बाजार के तौर पर देखती है तथा विद्यार्थियों को राष्ट्रीय नागरिक के स्थान पर श्भूमण्डलीय उपभोक्ताश समझती है तथा शिक्षण संस्थाओं को 'ज्ञान का कारखाना डिग्री डिप्लोमा fey' ही समझती है। इस प्रकार विश्वविद्यालय निगमित जगत का प्रशिक्षण स्थल बन गये हैं।

इस चुनौती का सामना करने के लिए भारत नें स्व–वित्तीय कालेजों और स्व–समर्थित पाठ्यक्रमों के लिए अनोखे कार्यक्रमों की शुरूआत की है और विभिन्न प्रकार की राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं व उद्योगपतियों से शिक्षा के प्रसार हेतु साझेदारी कर निवेश हेतु पहल की है, परिणामस्वरूप पिछले 15–20 वर्षों में स्व–वित्तीय इन्जीनियरिंग, मेडिकल, प्रबन्धन, कानून व शिक्षक प्रशिक्षण संस्थायें व विश्वविद्यालयों आदि में बेतहाशा बढ़ोत्तरी हुई है।

7 वीं अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 2017–18 में 78 प्रतिशत कालेज निजी प्रबंधित हैं, जिसमें 64.7 प्रतिशत कालेज निजी व गैर सहायता प्राप्त हैं तथा 13.3 प्रतिशत कालेज निजी व सहायता प्राप्त हैं। शेष 22 प्रतिशत कालेज ही मात्र सरकार द्वारा प्रबंधित हैं और भारत में निजी क्षेत्र द्वारा प्रबंधित गैर सहायता प्राप्त सर्वाधिक कालेज 82 प्रतिशत आन्ध्र प्रदेश व तेलंगाना, 76 प्रतिशत तमिलनाडु में हैं गैर सहायता प्राप्त निजी कालेजों की सबसे कम संख्या 12 प्रतिशत असम में है जबकि प्रथम ।ैभ्म रिपोर्ट के अनुसार 2010–11 में 73 प्रतिशत कालेज निजी प्रबंधित थे, शेष 27 प्रतिशत कालेज सरकार द्वारा प्रबंधित थे, इसी प्रकार 2010–11 में निजी क्षेत्र द्वारा प्रबंधित नर्सिंग कालेज 2133, पॉलीटेक्निक कालेज 3586, शिक्षक प्रशिक्षण कालेज 4923 थे जो कि पिछले आठ वर्षों में बढ़कर 2017–18 में नर्सिंग कालेज 2676, पॉलीटेक्निक कालेज 3239 व शिक्षक प्रशिक्षण कालेज 3691 हो गये, जिससे उच्च शिक्षा का प्रसार तो हुआ

eISSN 2581-8996
ONLINE
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED JOURNAL
Volume 08, Issue 02, July 2025

है, लेकिन गुणवत्ता सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है, साथ ही उच्च शिक्षा का महंगा हो जाना एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है।

निजी क्षेत्र के स्व–वित्तीय कालेजों, सार्वजनिक कालेजों और विश्वविद्यालय में स्व–वित्तीय पाठ्यक्रमों को भारत के मध्यम वर्ग में पसंद किया है, लेकिन सामाजिक सांस्कृतिक असमानता, आर्थिक विषमता, नैतिक मूल्यों का हास, गुणवत्ता में गिरावट, भ्रष्टाचार आदि के लिए इसकी आलोचना की जाती है, इनका एक मात्र उद्देश्य मुनाफा कमाना है तथा उद्योग व समाज की जरूरतों के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों की उन्हें विशेष परवाह नहीं होती। 21वीं सदी की शुरूआत में ही माँग व पूर्ति में असन्तुलन के कारण छंटनी के फलस्वरूप भारत और विदेशों के आई.टी. कर्मियों तथा साफ्टवेयर सलाहकारों को भी समस्याओं से गुजरना पड़ा, अभी भी भारत के निजी इन्जीनियरिंग, प्रबन्धन व शिक्षक प्रशिक्षण कालेजों में बहुत सी सीटें खाली रह जाने के समाचार मिले हैं।

आज मानव में सूचना संचार और तकनीकी की मदद से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार को जन्म देकर समग्र विश्व को संकुचित करके श्वैश्विक ग्राम में परिवर्तित कर दिया है। परिणामस्वरूप वैश्वीकरण की उत्पत्ति हुई यहां वैश्वीकरण शब्द का अर्थ विश्व के एकीकरण से है, अर्थात किसी वस्तु या विचार के सम्पूर्ण विश्व में प्रचलित व प्रसारित होने से है। इस प्रकार वैश्वीकरण में संसार के विभिन्न देशों द्वारा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र (आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक व तकनीकी आदि) में अन्तर्सम्बन्ध स्थापित कर परस्पर इनका आदान प्रदान करने पर बल दिया जाता है।

शिक्षा में वैश्वीकरण (भूमण्डलीकरण) का तात्पर्य संसार के विभिन्न देशों के मध्य एक दूसरे के शैक्षिक विचारों का आदान–प्रदान करने, एक दूसरे के देश में जाकर शिक्षा ग्रहण करने व एक दूसरे के देश में शैक्षिक संस्थायें स्थापित कर सहयोग करने से हैं। आज हमारे देश में विदेशी विश्वविद्यालयों से मान्यता प्राप्त अनेकों संस्थाएं संचालित हैं तथा हमारे देश के विश्वविद्यालयोंध बोडों से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं विदेशों में भी चल रही हैं। वैसे उच्च शिक्षा का अन्तर्राष्ट्रीयकरण कोई नई बात नहीं है। षविश्वविद्यालयष शब्द का मतलब ही अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा और ज्ञान का आदान–प्रदान करना होता है। प्राचीन भारत में तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय इसी प्रकार के थे, जहां विदेशों से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे।

पिछले कुछ वर्षों में विदेशी विद्यार्थियों का भारत की शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ा है। उच्च शिक्षा में 2012–13 में विदेशी विद्यार्थियों का कुल नामांकन 34774 था जो कि 2017–18 में बढ़कर 46144 हो गया, 166 देशों के विद्यार्थी यहां शिक्षा ग्रहण करने आये, जिसमें सर्वाधिक विद्यार्थी नेपाल से 11521 (25 प्रतिशत), अफगानिस्तान से 4378 (9.5 प्रतिशत), सूडान से 2020 (4.8 प्रतिशत) तथा भूटान से 1999 (4.3 प्रतिशत) थे। विदेशी छात्रों नें सर्वाधिक 77.4 प्रतिशत नामांकन स्नातक पाठ्यक्रमों (बी.टेक, बी.बी.ए.) तथा 14.8 प्रतिशत नामांकन परास्नातक पाठ्यक्रमों में कराया। जिससे यह स्पष्ट है कि विदेशी विद्यार्थी भारत के स्नातक पाठ्यक्रमों में विशेषकर बी.टेक व बी.बी.ए. में अधिक रूचि ले रहे हैं।

चूँकि उच्च शिक्षा सही ज्ञान की खोज की जगह बाजार बनती जा रही है। कई विश्वविद्यालय निजी सहयोगियों के साथ साझेदारी कर रहे हैं, जिससे उन्हें गैर शैक्षिक और तकनीकी सेवा दक्षता का लाभ मिल सके। उदाहरणस्वरूप यूरोप के 21 विश्वविद्यालयों में वित्त का आदान–प्रदान करने व निजी तकनीकी सेवाओं व व्यय कम करने के लिए आपस में समझौता किया लेकिन धन बचाने के उपायों का लाभ छात्रों

eISSN 2581-8996
ONLINE
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED JOURNAL
Volume 08, Issue 02, July 2025

को नहीं मिला, बल्कि उन्हें तो फीस में वृद्धि, आधुनिकतम तकनीक के क्रियान्वयन और बेहतर ढांचागत सुविधाओं के नाम पर पहले से ही कहीं अधिक फीस देनी पड़ रही है। वे आधुनिक तकनीक के नाम पर छात्रों व अभिभावकों को अधिकांशतः बलि का बकरा बनाते हैं।

आजकल भारत में निजी उच्चतर शिक्षा एक बहुत बड़ा धन्धा बन गई है तथा शैक्षिक संस्थान उत्पाद की खरीद–बिक्री के लिए बाजार बन गये हैं और उनके छात्र–छात्रायें उपभोक्ता व ग्राहक बन गये हैं। आज पूरे विश्व के निजी विश्वविद्यालय के छात्र–छात्राओं विशेषतः विदेशी छात्र–छात्राओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के लालच दे रहे हैं। बहुसंस्कृति व विविधताओं की दुहाई दे रहे हैं। लेकिन यह निर्विवाद सत्य है कि इसके पीछे इनका प्रमुख लक्ष्य अतिरिक्त धन इकटठा करना है। ऐसे संस्थान विद्यार्थियों से महंगी फीस लेते हैं। समय–समय पर जाली विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों व डिग्रियों की खबरें भी सुनने को मिलती हैं, हिन्दुस्तान टाइम्स में छपी खबर के अनुसार जाली बी.एड. डिग्री मामले में प्रत्येक डिग्री के लिए निजी संस्थानों द्वारा ढाई लाख रूपये वसूल किया गया। कई बार यह विदेशी बैनर के नाम पर भी होता है। निजी और वाणिज्य क्षेत्र के छात्र–छात्राओं को बेहतर रोजगार की सम्भावना का लालच देकर अपनी ओर आकर्षित करते हैं और शिक्षकों को खरीद कर उनकी शैक्षिक एकजुटता (।बंकमउपब ैवसपकंतपजल) का खण्डन करते हैं। वे शिक्षा के व्यापार को बने रहने के लिए साम, दाम, दण्ड, भेद सभी नीतियों को अपनाते हैं। पहले ज्ञान का निःशुल्क सृजन व प्रसारण होता था, निजी व सार्वजनिक क्षेत्र दोनों ही बिना रूकावट के इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन अब बौद्धिक सम्पदा के नाम पर कृत्रिम दीवार खड़ी की जा रही है। इण्टरनेट पर अधिकांश महत्वपूर्ण सूचनायें व लेख भी बिना कीमत के उपलब्ध नहीं हैं। अतः उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण के लाभों को निम्नलिखित ढंग से स्पष्ट किया जा सकता है :–

- गुणवत्तायुक्त विश्वस्तरीय आद्यतन उच्च शिक्षा उपलब्ध कराना।
- निगमित विश्वविद्यालय, सामुदायिक विश्वविद्यालय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालयों की स्थापना करना।
- ज्ञान के स्थान पर कौशलों के विकास पर बल देना।
- दूरस्थ शिक्षा व ई–लर्निंग को बढावा देना।
- सूचना एवं सम्प्रेषण में आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करना।
- शिक्षा के उद्देश्यों, पाठ्यक्रमों, शिक्षण विधियों व मूल्यांकन प्रणाली में व्यापक परिवर्तन आना।
- विद्यार्थियों व अभिभावकों की अभिवृत्ति को व्यापक व वैज्ञानिक बनाना।
- उच्च शिक्षा के प्रसार हेतु आवश्यक वित्तीय संसाधनों को जुटाना।
- रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना।
- विभिन्न प्रकार की समसामयिक चुनौतियों (आतंकवाद, पर्यावरण) से निपटने में सहायक होना।
- उच्च स्तरीय शोध सम्पन्न करने में विश्व समुदाय का सहयोग प्राप्त करना।

दोष :–

- उच्च शिक्षा का व्यापारीकरण व बाजारीकरण होना।
- उच्च शिक्षा का अत्यधिक महंगा होना।

eISSN 2581-8996
ONLINE
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED JOURNAL
Volume 08, Issue 02, July 2025

- शिक्षण संस्थाओं का श्ज्ञान की फैक्ट्रीश व श्डिग्री डिप्लोमा मिलश बन जाना।
- गुणवत्ता का हास होना।
- शैक्षिक, सामाजिक व आर्थिक विषमता को बढ़ावा मिलना।
- आदर्श नागरिक के स्थान पर श्भूमण्डलीय उपभोक्ताश तैयार करना।

सुझाव :– उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उदारीकरण, निजीकरण व भूमण्डलीकरण को लागू करना आज वक्त की मांग है, लेकिन इसे बहुत ही सावधानीपूर्वक लागू किया जाये और इसके दुष्प्रभावों को कम करने की चेष्टा की जाये। इसे लागू करने में निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखा जाये–

- आज निजी एवं विदेशी शिक्षा के सन्दर्भ में भारत सरकार को उचित नीति निर्धारित करने की जरूरत है, तेजी से बदलते विश्व परिदृश्य में न तो निजी शिक्षा का बहिष्कार सम्भव है और न वांछनीय ।
- उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लचीली व्यवस्था अपनाते हुए सृजनात्मक नूतन व नवीकरणयुक्त विचारों का स्वागत करना चाहिए।
- आज उच्च शिक्षा को जन–जन तक पहुंचाने की बजाय उसे उनके लिए अधिक उपयोगी व सार्थक बनाया जाना चाहिए।
- उच्च शिक्षा के वर्तमान पाठ्यक्रम को अधिक छात्र केन्द्रित बनाते हुए बाजार उपयोगी व बहुमुखी बनाना अधिक तर्कसंगत होगा।
- उच्च शिक्षा के व्यापारीकरण व बाजारीकरण को कानून बनाकर तुरन्त रोका जाना चाहिए।
- उच्च शिक्षा के प्रसाद व उचित प्रबन्धन हेतु सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) मॉडल को
- सावधानीपूर्वक लागू किया जाना चाहिए।
- सामुदायिक महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए।

निष्कर्ष :– आज वैश्वीकरण नें उच्च शिक्षा में अनेकोंनेक नूतन आयामों को जन्म दिया है। भारत में विदेशों से शिक्षा ग्रहण करने आने वाले विद्यार्थियों की संख्या में भी लगातार वृद्धि हो रही है तथा भारत से भी बड़ी संख्या में विद्यार्थी विदेशों में शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं। उच्च शिक्षा के उद्देश्यों, पाठ्यक्रमों, शिक्षण विधियों व मूल्यांकन प्रणाली में व्यापक परिवर्तन आया है और हम सूचना व सम्प्रेषण (प्ब्ज्) की आधुनिकतम प्रौद्योगिकी का प्रयोग शिक्षा में कर रहे हैं। मुक्त व दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा दे रहे हैं। ऑनलाइन प्रवेश तथा परीक्षाएं संचालित की जा रही हैं और ई–लर्निंग व वर्चुअल विश्वविद्यालयों की संकल्पना साकार हो रही है। इन्टरनेट व ब्राडबैण्ड की सहायता से दुनिया भर की साहित्य सामग्री घर बैठे पढ़ सकते हैं। यह सब वैश्वीकरण का ही परिणाम है, जिसने सीमायी बन्धनों को संकुचित कर बहुमुखी विकास की राह आसान की है। आज उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्र में प्रवेश से उच्च शिक्षा का प्रसार तो हुआ है, किन्तु इसका लाभ चन्द मुटठी भर धनिक लोगों को ही हुआ है। अतः उच्च शिक्षा का व्यापारीकरण, बाजारीकरण, गुणवत्ता हास व शैक्षिक विषमता को रोका जाना चाहिए तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयासों, सार्वजनिक निजी भागीदारी (च्च्च् मॉडल), राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्थाओं से अधिकाधिक सहयोग प्राप्त कर उसका लाभ उठाया जाय, साथ ही उनसे उत्पन्न कठिनाइयों से प्रभावी ढंग से उचित नीति बनाकर निबटा जाय।

eISSN 2581-8996
ONLINE
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED JOURNAL
Volume 08, Issue 02, July 2025

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :–

गुप्ता एस.पी. (2015). भारतीय शिक्षा का इतिहास विकास एवं समस्याएं, इलाहाबाद शारदा पुस्तक भवन.

गुप्ता आशा : उच्चतर शिक्षा के बदलते आयाम, दिल्लीरू हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय.

विश्वविद्यालय, दिल्ली–2011

दैनिक जागरण, 24 जून, 2014

नवभारत टाइम्स, 10 दिसम्बर, 2014